शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल और 12 वीं की एक मई से

माशिमं भोपाल ने जारी किया टाइम-टेबल

भोपाल, (प्रसं)। मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा शनिवार को यहां वर्ष 2021 के लिए होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल से तथा बारहवीं की परीक्षा एक मई से आयोजित की जाएगी।

हाईस्कूल परीक्षा 30 अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 मई को समाप्त होगी। इसी तरह हायर सेकंडरी परीक्षा एक मई से शुरू होकर 18 मई को समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में सुबह 07. 30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्षा में प्रातः 07. 45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हाई स्कूल, हायर सेकंडरी, हायर सेकंडरी पाठ्यक्रम परीक्षा, कार्यक्रम घोषित किए गए हैं।

10वीं का परीक्षा कार्यक्रम

30 अप्रैल- विशिष्ट भाषा हिंदी

1 मई- नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय

3 मई- सामाजिक विज्ञान

4 मई- विशिष्ट भाषा उर्दू तृतीय भाषा सामान्य उर्दू

5 मई- विशिष्ट भाषा संस्कृत

6 मई- तीसरी भाषा मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, केवल मूक बधिर छात्रों के लिए पेंटिंग और दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत

8 मई- विज्ञान

11 मई- विशिष्ट भाषा अंग्रेजी, द्वितीय व तृतीय भाषा अंग्रेजी

15 मई - गणित

12वीं का परीक्षा कार्यक्रम

1 मई- विशिष्ट भाषा हिंदी एवं द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी

3 मई- विशिष्ट भाषा संस्कृत एवं द्वितीय भाषा सामान्य संस्कृत

4 मई- फिजिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान के तत्व

5 मई- विशिष्ट भाषा उर्दू, द्वितीय भाषा सामान्य उर्दू

6 मई- विशिष्ट भाषा अंग्रेजी

8 मई- एनएसक्यूएफएवं शारीरिक शिक्षा

10 मई- भूगोल एवं क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर

11 मई- बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी

12 मई- समाजशास्त्र मनोविज्ञान कृषि मानविकी

13 मई- केमिस्ट्री इतिहास व्यवसाय अध्ययन ड्राइंग एंड पेंटिंग

17 मई- मैथमेटिक्स

18 मई-भारतीय संगीत

एमपी बोर्ड: विशिष्ट हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

एमपी बोर्ड ने शनिवार को 10- 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दोनों परीक्षाएं विशिष्ट हिंदी के पेपर से शुरू होंगे। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और 12वीं की परीक्षा एक मई से 18 मई तक आयोजित होगी।

इसी तरह शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा और डीपीएसई परीक्षा 30 अप्रैल से 11 मई तक चलेगी। बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे तक होंगी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को सुबह 7.30 बजे उपस्थित होना होगा। 7.45 बजे के बाद किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।

6वीं से 8वीं की परीक्षा पर फैसला कल: स्कूल शिक्षा मंत्री सोमवार को कक्षा 6वीं और 8वीं की परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षाओं पर निर्णय होगा।

12वीं का टाइम टेबल समय: सुबह 8 से 11 बजे तक

तारीख	प्रश्नपत्र
1 मई	विशिष्ट भाषा - हिंदी, द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी वोकेशनल सहित।
3 मई	विशिष्ट भाषा - संस्कृत, द्वितीय भाषा सामान्य संस्कृत वोकेशनल सहित।
4 मई	फिजिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, एनिमल हसबेंड्री मिल्क एंड ट्रेड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स।
5 मई	विशिष्ट भाषा उर्दू, द्वितीय भाषा सामान्य उर्दू वोकेशनल सहित।
6 मई	विशिष्ट भाषा सामान्य अंग्रेजी, द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी वोकेशनल सहित।
8 मई	नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन के विषय, शारीरिक शिक्षा, प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स।
10 मई	भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, स्टील लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया-विज्ञान एवं स्वास्थ्य, बुक-कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तृतीय प्रश्न-पत्र वोकेशनल कोर्स।
11 मई	बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी।
12 मई	समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि (मानविकी), होम साइंस, एनवायरनमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, इनफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस।
13 मई	कैमिस्ट्री, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलीमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान।
17 मई	मैथमेटिक्स।
18 मई	भारतीय संगीत, राजनीति शास्त्र।

10वीं का टाइम टेबल समय: सुबह 8 से 11 बजे तक

तारीख	प्रश्नपत्र
30 अप्रैल	विशिष्ट भाषा हिंदी, द्वितीय व तृतीय भाषा सामान्य हिंदी।
1 मई	एनएसक्यूएफ के समस्त विषय।
3 मई	सामाजिक विज्ञान
4 मई	विशिष्ट भाषा उर्दू, तृतीय भाषा सामान्य उर्दू।
5 मई	विशिष्ट भाषा संस्कृत, द्वितीय व तृतीय भाषा सामान्य संस्कृत।
6 मई	तृतीय भाषा सामान्य मराठी, गुजराती, पंजाबी व सिंधी, केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए पेंटिंग, केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत।
8 मई	विज्ञान
11 मई	विशिष्ट भाषा अंग्रेजी, द्वितीय और तृतीय भाषा सामान्य अंग्रेजी।
15 मई	गणित

केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आज, एडमिट कार्ड जारी

भोपाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को आयोजित की जा रही है। इसके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर दिए गए हैं। पेपर-1 में 150 मार्क्स के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे।

इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स, एनवायरनमेंटल स्टडीज से जुड़े 30-30 प्रश्न पूछ जाएंगे। वहीं पेपर-2 में भी 150 मार्क्स के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स व साइंस (मैथ्स व साइंस के टीचरों के लिए) या सोशल स्टडीज/सोशल साइंस (सोशल स्टडीज/ सोशल साइंस टीचर के लिए) से जुड़े प्रश्न पूछ जाएंगे।

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी: प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एमपी पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट शुरू होने से पहले बैठने की जगह को पूरी तरह सेनिटाइज किया जाएगा। 2 सीटों के बीच गैप रखा जाएगा। स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दस्ताने पहनने वाले पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले सभी शीट पर रफ कॉपी, शीट को रखा जाएगा।

चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति नहीं होने पर सौंपा ज्ञापन

पिछोर(नईदुनिया न्यूज)। गत दिवस एक दिवसीय प्रवास पर पिछोर पहुंचे गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से चयनित शिक्षकों ने मुलाकात की और नियुक्ति कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

चयनित शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से गृहमंत्री को वताया कि चयन होने के वाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाने से अभ्यर्थी वेरोजगार होकर दर-दर भटक रहे हैं। नियुक्ति को लेकर उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार कोई न कोई वहाना वनाकर शिक्षकों की नियुक्ति करने से टाल रही है। चयनित शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे रमन पुरोहित ने वताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आपको प्रदेश का मुखिया और मामा वनकर कहते हैं कि जव तक मैं जिंदा हूं तव तक किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं हैं परंतु उनकी कथनी और करनी में अंतर लग रहा है।उन्होंने वताया कि शासन द्वारा 8 साल वाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई थी। इस अवसर पर रमन पुरोहित, शैलेश रहोरा, शिखा पाठक, मनीषा शर्मा, रक्षा सोनी, दीपमाला त्रिपाठी, उमा पुरोहित, नूरजहां वानो, अंजली गुप्ता, गीता भट्ट, रानी पाठक, सुनील लोधी, प्रदीप अहिरवार, सुखवीर वंशकार, कमलेश कोली, नीतू कोली, कवीर कोली, रानी पाठक, सत्यांश गुप्ता, संस्कार सोनी, स्कंधा खान सहित चयनित शिक्षक उपस्थित रहे।

भास्कर

परीक्षा • राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली से आठवीं तक के बच्चों की परीक्षा व रिजल्ट की तैयारी की

मार्च तक स्कूली बच्चों के 3 ओपन बुक टेस्ट

भास्कर संवाददाता | दतिया

स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं कक्षा तक की परीक्षा और फाइनल रिजल्ट की तैयारी कर ली है। इस बार कक्षा तीसरी से आठवीं तक के जनवरी से मार्च तक तीन ओपन बुक टेस्ट होंगे। तीनों टेस्ट के प्राप्तांकों से फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके लिए प्रश्नपत्र की पुस्तिका छपकर तैयार हैं।

जिले में पहली से तीसरी तक के छात्रों को इस बार पाठ्य पुस्तक की जगह अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी। इसी से वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट बनेगा। हर माह टेस्ट के शेड्यूल भी राज्य शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। इस बार विभाग ने इन कक्षाओं की परीक्षा को मूल्यांकन नाम दिया है। जिलेभर में कक्षा एक से आठवीं तक के 1 लाख 90 हजार बच्चे हैं, जिनकी यह परीक्षाएं कराई जाना है। स्कूलों तक वर्कशीट भेजी जा चुकी है। कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चे वर्कशीट हल करेंगे। इन कक्षाओं की परीक्षा को इस बार मूल्यांकन नाम दिया गया है। इसके अलावा बीआरसीसी, प्राचार्य, बीईओ, बीएसी और जनशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड-19 की गाइड के अनुसार जिला शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रश्न पुस्तिका 30 तक छात्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य

20 जनवरी को प्रश्न पुस्तिका का वितरण किया गया था, जिसको 30 जनवरी तक स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाना है । 3 फरवरी तक प्रश्न पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी। फरवरी और मार्च में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तीनों माह के रिजल्ट एकजाई कर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट बनाया जाएगा।

ऐसे होगी परीक्षाः तीसरी से आठवीं कक्षा तक अलग-अलग प्रश्न पत्रों की पुस्तिका बनेगी। एक प्रश्न पुस्तिका में कक्षा अनुसार सभी विषयों के प्रश्न पत्र रहेंगे। शिक्षक बच्चों तक प्रश्न पुस्तिका पहुंचाएंगे, जिन्हें छात्र घर पर हल करेंगे, फिर प्रश्न पुस्तिका में उत्तर लिखकर स्कूल में जमा करेंगे।

वर्कशीट भेज रहेः एपीसी संजीव विश्वदेवा ने बताया कि प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें सभी विषयों के प्रश्नपत्र शामिल किए जाएंगे। जनवरी से मार्च के बीच ओपन बुक टेस्ट कराकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

आयुक्त शिक्षा के हिटलरशाही आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज बैहर।

ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर के मार्गदर्शन में लोक शिक्षण संचालनालय के निर्धारित परीक्षा परिणाम के लक्ष्य को पूरा न कर पाने वाले प्राचार्यों, शिक्षकों पर प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में बालाघाट जिला में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महेन्द्र नागेश्वर के नेतृत्व में एकत्र सैकड़ों शिक्षकों ने बैहर एसडीएम श्री गुरु प्रसाद को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त आदेश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और आदेश निरस्त करने की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि कोरोना काल में महिनों विद्यालयों की पढ़ाई ठप पड़ी रही। ऐसे में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्धारित परीक्षा परिणाम के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत से विद्यालयों में मुमकिन नहीं है। इसके बाद भी हम शिक्षक निर्धारित से बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। शासन को भी अपनी ओर से सभी विद्यालयों में 100% बच्चों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन शिक्षकों की ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के बाद भी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, तो इसके लिए सिर्फ शिक्षकों को दोषी मानकर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना एकदम अनुचित और व्यावहारिक है। ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन शिक्षकों के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई का सड़क और कोर्ट दोनों जगह खुलकर विरोध करेगा।

ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष चंदन विष्कर्मा ने बताया कि शिक्षकों को मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय से एक के बाद आदेश जारी किए जा रहे हैं। शिक्षक शासन द्वारा निर्धारित कोर्स के साथ ही विद्यालय में पढ़ाने की नई नई गतिविधियों, अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन, मासिक टेस्ट, प्री टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा आदि विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। एक ओर शासन द्वारा बेस्ट ऑफ फाइव, वर्तमान में छात्रावासों को बंद रखने, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति स्वेच्छिक करने, बच्चों को अधिक प्राप्तांक के लिए दबाव ना डालने, शारीरिक या मानसिक रूप से दंडित नहीं करने के सख्त निर्देश हैं, वहीं दूसरी ओर कम परीक्षा परिणाम के लिए सीधे शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन करता है कि शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और समाज में अपमानित करने वाले आदेशों की बजाय, शिक्षकों के साथ बैठकर बुनियादी समस्याओं पर चर्चा कर ठोस शिक्षा गुणवत्ता नीति का निर्माण करना चाहिए। कार्यक्रम में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेन्द्र नागेश्वर , उपाध्यक्ष शुभ्री आर परते , सचिव अनिल वहने, बैहर ब्लॉक अध्यक्ष गीतेश रहागडल , मोहित मोहन श्रीवास्तव, जायसवाल सर, पटले, दिलीप सर, दिनेश पटले, जमने सर, सहित सैकड़ों शिक्षकों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा।

परीक्षाः स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा एक से 8 वीं तक के छात्रों की परीक्षा और रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू

मार्च तक स्कूली बच्चों के तीन ओपन बुक टेस्ट होंगे

- एकजाई कर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट बनाया जाएगा।

हरिभूमि न्यूज ▶▶विदिशा

स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा पहली से आठवीं तक की परीक्षा और फाइनल रिजल्ट तैयार करने की तैयारी कर ली है। इस बार कक्षा तीसरी से आठवीं तक के जनवरी से मार्च तक तीन ओपन बुक टेस्ट होंगे। तीनों टेस्ट के प्राप्तांकों से फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके लिए प्रश्नपत्र की पुस्तिका छपकर तैयार है। पहली से तीसरी तक के स्टूडेंट्स को इस बार पाठ्य पुस्तक की जगह अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी। इसी से वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट बनेगा। हर माह टेस्ट का शेड्यूल भी राज्य शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। इस बार विभाग ने इन कक्षाओं की परीक्षा को मूल्यांकन नाम दिया है। 20 जनवरी को प्रश्न पुस्तिका का वितरण किया गया था, जिसको 30 जनवरी तक स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाना है। 3 फरवरी तक प्रश्न पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी। फरवरी और मार्च में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तीनों माह के रिजल्ट एकजाई कर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट बनाया जाएगा।

डाइट केंद्र पर स्टाफ को दिया जाएगा प्रशिक्षण

स्कूलों तक वर्कशीट भेजी जा चुकी है। कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चे वर्कशीट हल करेंगे। इन कक्षाओं की परीक्षा को इस बार मूल्यांकन नाम दिया गया है। इसके अलावा बीआरसीसी, प्राचार्य, बीईओ, बीएसी और जनशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोविड- 19 की गाइड के अनुसार डाइट प्रशिक्षण केंद्र पर सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ऐसे होगी परीक्षा

- तीसरी से आठवीं कक्षा तक अलग-अलग कक्षा के प्रश्न पत्रों की पुस्तिका बनेगी।
- एक प्रश्न पुस्तिका में कक्षा के अनुसार सभी विषयों के प्रश्न पत्र रहेंगे।
- स्कूल के शिक्षक स्टूडेंट्स तक प्रश्न पुस्तिका पहुंचाएंगे, जिन्हें स्टूडेंट अपने घर पर अभिभावकों की मदद से हल करेंगे।
- प्रश्न पुस्तिका में उत्तर लिखकर स्टूडेंट स्कूल में जमा करेंगे।

परीक्षा परिणाम का प्रतिशत तय करने के आदेश का विरोध, सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ खरगोन

शासन द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी में छात्र/ छात्राओं के परीक्षा परिणाम के साथ ही प्रतिशत तय करने के आदेश का विरोध शुरु हो गया है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन एवं अपाक्स ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौपकर इस आदेश को अजीब व हैरतभरा करार देते हुए निरस्त करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष अतीक खान ने कहा कि शासन द्वारा जारी आदेश से शिक्षक हैरत में है। इस सत्र में स्कूल 7 माह बंद रहे, विगत 18 दिसंबर से पालको कि सहमति से केवल बच्चे आ सकते हैं, जिसमें आधे से भी कम बच्चे आ रहे हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में शिक्षकों को 9वीं में 59 प्रतिशत, 10वी में 64 प्रतिशत, 11बी का 81प्रतिशत एवं 12वी का 73 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने की शर्त रखी है, इसके अतिरिक्त छात्र वॉर भी एडवांस परिणाम चाहा गया है जो हास्यास्पद है। ऐसे आदेश शिक्षको का मनोबल तोडने साथ ही शिक्षा को मजाक बनाने जैसा प्रतीत होता है। इसे निरस्त किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।

दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर में शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट

दस महीने बाद, कई राज्यों में कल से खुलेंगे स्कूल

एजेंसी • नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगभग 10 महीने से ज्यादा समय से बंद स्कूल-कॉलेजों को अब धीरे-धीरे खोला जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात तथा जम्मू-कश्मीर में 1 फरवरी 2021 यानी सोमवार से स्कूल-कॉलेज खुल जाएंगे। सभी राज्यों ने स्कूलों को खोलने संबंधी प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं।

हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल: हरियाणा में छठी से आठवीं क्लास तक के स्कूल एक फरवरी से खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि छात्रों को किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र लाना होगा कि उनमें कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है।

वहीं प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू होने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

तेलंगाना में सीनियर छात्र आएंगे स्कूल: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लासेस तक के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में भी तैयारी: जम्मू-कश्मीर में 1 फरवरी से समर जोन के स्कूल खोल दिए जाएंगे। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत होगी।

गुजरात में खुलेंगे स्कूल: गुजरात में 1 फरवरी से कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूल में केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को ही आने की इजाजत दी गई है।

दिल्ली में 5 फरवरी से खुलेंगे: दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए 5 फरवरी से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा संस्थानों को भी खोल दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में पहली से 8वीं तक के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन: छत्तीसगढ़ में पहली से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा छात्रों को 'पढ़ई तुंहर दुआर' अभियान के तहत प्रमोट किया जाए।

हायर सेकंडरी और हाई स्कूल परीक्षार्थियों की संख्या घटी

पीपुल्स संवाददाता • शिवपुरी

editor@peoplessamachar.co.in

कोरोना के कारण इस साल हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूलों का नियमित संचालन महज महीने भर पहले शुरू हुआ था। यही कारण है कि इस बार परंपरागत तौर पर मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं करीब दो महीने बिलंब से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शनिवार को परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके अनुसार हाई स्कूल की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेंगी, जबकि हायर सेकेण्डरी की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होकर 18 मई तक चलेंगी। दोनों ही परीक्षाओं का आयोजन सुबह 8 से 11 बजे की पाली में किया जाएगा। इसके अलावा डीपीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 30 अप्रैल, जबकि द्वितीय वर्ष की एक मई से शुरू होंगी।

इस साल 7 हजार 921 परीक्षार्थी घटे

कोरोना का प्रभाव जिले में हाई व हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के परीक्षार्थियों की संख्या पर भी नजर आ रहा है। परीक्षा प्रभारी विमल श्रीवास्तव के अनुसार इस साल हाई स्कूल परीक्षा में 21 हजार 805 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो पिछले वर्ष की संख्या से 5 हजार 97 कम हैं। इसी तरह हायर सेकेण्डरी में इस बार 13 हजार 631 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो बीते सत्र से 2 हजार 824 कम हैं। इस तरह जिले में पिछले साल की तुलना में 7 हजार 921 परीक्षार्थी इन दोनों परीक्षाओं में घटे हैं।

परीक्षा केंद्र भी होंगे कम

इस साल शुरूआत में विभाग ने अब तक जिले में बनने वाले 68 परीक्षा केंद्रों को और बढ़ाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन शनिवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया द्वारा परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के चलते केंद्र कम करने व छोटे केंद्रों को पड़ौस के केंद्र में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग नए सिरे से केंद्रों के गठन में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इस बार केंद्रों की संख्या 68 की बजाय घट कर 60 के आसपास रह सकती है। बता दें कि बीते साल 68 केंद्रों में से 65 हाई व हायर सेकेण्डरी दोनों के थे, जबकि 3 केंद्र ऐसे थे, जहां सिर्फ हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी।

इनका कहना है

इस बार परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। व्हीसी में दिए निर्देशों के क्रम में केंद्रों की संख्या कुछ कम की जा सकती है, इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं।

दीपक पांडे, डीईओ

विद्यार्थी जहां अध्ययन कर रहा, वहीं पर होंगी उसकी परीक्षाएं

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार परीक्षा पद्धति में किया बड़ा बदलाव

शासन द्वारा घोषित अवकाश में भी परीक्षाएं यथावत रूप से चलेंगी

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

घातक कोरोना आपदा को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार की परीक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव किया है। परीक्षा टाइम टेबल जारी करने के साथ.साथ मंडल ने समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि इस बार यदि शासन कोई अवकाश घोषित करता भी है तभी परीक्षाओं का क्रम अनवरत रूप से चलेगा। इस बार परीक्षाओं में अध्ययन संस्थान नहीं परिवर्तित की जाएगी।

मंडल सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संचालित समस्त परीक्षाएं प्रातः 8 बजे से 11 के मध्य संपन्न कराई जाएंगी। निमित्त स्वाध्याय दृष्टिहीन मूकबधिर परीक्षार्थियों की परीक्षाएं समान रूप से एक ही तिथि और दिवस में होंगी। मंडल का कहना है कि पूरा कार्यक्रम वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। मंडल से मान्यता प्राप्त समस्त प्राचार्य को भी निर्देश दिए गए हैं कि घोषित परीक्षा कार्यक्रम से समस्त छात्रों को अवगत कराया जाए। मंडल के परीक्षा कार्यक्रम को शाला के नोटिस बोर्ड पर भी चश्मा करना होगा। निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्यक्रम को कृपया भली.भांति नोट किया जाए। परीक्षा कार्यकाल में शासन द्वारा यदि कोई साप्ताहिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। तब भी परीक्षाएं यथावत चलेगी। नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षा उनके विद्यालय एवं स्वाध्याय छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं परीक्षा केंद्र पर ही संचालित की जाएंगी।

संक्रमण से बचाव के लिए किया गया है बदलाव

बताना होगा कि पिछले कुछ सालों से माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा प्रणाली में बदलाव करता रहा है। विद्यार्थी जहां अध्ययन करता था वहां पर परीक्षा ना कराते हुए दूसरे विद्यालयों में सेंटर स्थापित किया जाता रहा है।

मंडल में अधिकारियों का कहना है कि करुणा का संक्रमण प्रदेश में अभी भी कम नहीं हुआ है। अगर अध्ययन संस्था बदलती है तो जहां विद्यार्थियों को आवाजाही में परेशानी होगी वही भीड़ भी नुकसान का कारण बन सकती है। बढ़ती संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस बार नियमित विद्यार्थी जहां पढ़ रहे हैं वहीं पर उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। टाइम टेबल जारी करने के साथ.साथ प्राचार्य को भी इस संदर्भ में सूचित कर दिया गया है।

आवश्यकता पड़ने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा तिथियों में बदलाव भी कर सकता है

आपदा के समय माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षाएं जरूर कराने जा रहा हैए लेकिन जवाबदार अधिकारियों के बीच अभी भी कहीं ना कहीं महामारी को लेकर दहशत फैली हुई है। शनिवार को टाइम टेबल घोषित करने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव भी किया जा सकता है। कारण साफहै कि महामारी को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल अभी भी डरा हुआ है। कारण भी है कि पिछले सत्र की परीक्षाएं चल रही थी तभी कोर उन्होंने अचानक दस्तक दी थी। जब संक्रमण का प्रकोप बढ़ा दो माध्यमिक शिक्षा मंडल को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं बंद

कलेक्टर ने स्कूल में मध्याह्न भोजन खाकर देखा बोले-शिक्षक पढ़ाने में लापरवाही नहीं बरतें

जायजा ● कलेक्टर ने स्कूल, छात्रावासों का निरीक्षण किया, दो शिक्षक निलंबित किए

बड़ौदा (नईदुनिया न्यूज)। कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को बड़ौदा क्षेत्र के स्कूल, छात्रवास, स्वास्थ्य केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान ललितपुरा में चार लोगों को बीपीएल आवेदनों की जांचकर कर उनके बीपीएल राशन कार्ड बनवाए। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल में बच्चों के लिए बन रहे मध्याह्न- भोजन को भी चखकर देखा। इसके अलावा प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षक राकेश पारोंदिया को निलंबित किया गया है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ राजेश शुक्ल, बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक, पीओ जिला पंचायत पीएस राजपूत उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान सबसे पहले कलेक्टर ने ललितपुरा, मकडावदा कलां, सुवरा, पटना गांव में स्थित सरकारी मिडिल स्कूलों एवं छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। इसी प्रकार ग्राम ललितपुरा में मिडिल स्कूल में एनआरएलएम के सिलाई सेंटर एवं आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में रोटियां अच्छे से सेंककर देने के लिए कहा। उप स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुरा का निरीक्षण कर दवाईयों के स्टॉक को चैक किया। साथ ही अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं

बड़ौदा क्षेत्र के ललितपुरा सरकारी स्कूल में मध्याह्न- भोजन चेक करते कलेक्टर। ● नईदुनिया

के बारे में ग्रामवासियों से चर्चा की। ग्रामीण रामकथा बाई प्रजापति द्वारा बीपीएल राशनकार्ड बनाए जाने के लिए अवगत कराया। जिस पर से कलेक्टर ने बीपीएल की पात्रता की जांच कर तहसीलदार को राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत मकडावदा कलां में पंचायत के खाते में 20 लाख रुपये निर्माण राशि होने के बाद लंबे समय से राशि का उपयोग नहीं किया गया। इस पर राशि का शीघ्र उपयोग करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव को दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों की पेंशन शुरू कराई जाए।

निरीक्षण में यह मिले अनुपस्थित

कलेक्टर ने शामावि ललितपुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षक दिनेश गौतम, आशुतोष उमरिया एवं भृत्य संगीता आदिवासी अनुपस्थित पाई गई। जिनके खिलाफ डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मकडावदाकला में स्कूल के निरीक्षण में प्रभारी प्राचार्य जितेन्द्र मित्तल, शिक्षक अशोक पारेता, जगदीश प्रसाद अनुपस्थित मिले। अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास के औचक निरीक्षण में छात्रावास बंद पाया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग रयोपुर को छात्रावास बंद मिलने पर कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। सुवरा उप स्वास्थ्य केन्द्र, शाप्रावि एवं शामावि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षक राकेश पारोंदिया, सहायक शिक्षक छविराम जाटव अनुपस्थित पाए गए। जिनके खिलाफ सहायक आयुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इनमें से प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षक राकेश पारोंदिया को निलंबित किया गया। पटना के प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शाला में एक ही शिक्षक होने पर अन्य शिक्षक की व्यवस्था करने के निर्देश डीईओ को दिए।

शिक्षक की करतूत, स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर राष्ट्रध्वज का अपमान किया

पोहरी के बटकाखेड़ी स्कूल का मामला, अधिकारी बोले कार्रवाई करेंगे

पीपुल्स संवाददाता • शिवपुरी
editor@peoplessamachar.co.in

कोरोना के कारण पिछले साल मार्च से प्रायमरी और मिडिल स्कूल बंद हैं, बच्चों को स्कूल बुलाने व पढ़ाने पर प्रतिबंध है। इस आदेश के बाबजूद पोहरी क्षेत्र के भटनावर संकुल अंतर्गत आने वाले बटकाखेड़ी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने न केवल स्कूल में बिना सुरक्षा मापदंडों के बच्चों को बुलाकर कक्षा लगाई, बल्कि ध्वज संहिता का उल्लंघन कर राष्ट्रध्वज का भी अपमान किया है। शिक्षक के इस कृत्य का फोटो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है।

आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाने के बाद वे जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं।

राष्ट्रध्वज उतारकर कुर्सी पर रख दिया

जो फोटो वायरल हो रहा है, उसे 26 जनवरी का बताया जा रहा है, इस फोटो में बटकाखेड़ी स्कूल की इमारत नजर आ रही है और चबूतरे पर करीब दर्जन भर बच्चे बिना मास्क और असुरक्षित दूरी के बैठे हैं और शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा है। उसका नाम इकबाल खान बताया जा रहा है। इतना ही नहीं शिक्षक के समीप ही एक कुर्सी पर नियमों को ताक पर रख कर राष्ट्रध्वज कुर्सी पर पड़े अन्य सामान के बीच रखा है और पास ही झंडा का डंडा भी रखा है, जिससे अंदाज लगाया जा रहा है कि शिक्षक ने औपचारिक ध्वजारोहण के बाद उसे तत्काल उतार कर ध्वजसंहिता का पालन किए बगैर ऐसे ही रख छोड़ा। बता दें कि फिलहाल बच्चों को स्कूल में पढ़ाने बुलाने की मनाही है। शिक्षकों को उन्हें ऑन लाइन या फिर दो-तीन की संख्या में मोहल्ला क्लास लगाकर पढ़ाना है।

इधर रातौर में दुकान में चलती मिली क्लास

इधर जिला मुख्यालय से सटे रातौर गांव में एक छोटी से दुकान में 25 से 30 छोटे बच्चों को कोचिंग के नाम पर बिना सुरक्षा मापदंडों के पढ़ाने का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये मां शारदा नाम का कोई निजी स्कूल है, जिसे प्रतिबंध के चलते कोचिंग के नाम पर संचालित किया जा रहा है। जब नियमों के संबंध में बच्चों को पढ़ा रही शिक्षिका से सवाल किया गया तो उसने बच्चों को दुकान की शटर डालकर अंदर बंद कर दिया।

स्कूल में बच्चों को बुलाकर पढ़ाने और राष्ट्रध्वज अपमान का मामला जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, हम उसकी जांच करा रहे हैं। इसके बाद शिक्षक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दीपक पांडे, डीईओ

विद्यार्थियों-शिक्षकों ने मौन रहकर किया अध्ययन-अध्यापन

बापू की पुण्यतिथि पर मॉडल स्कूल में आयोजन

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बीते 61 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां मौन रहकर की संपादित की गईं। सुबह 11 बजे हूटर बजते ही विद्यालय में मौन शुरू हो गया, जो 1:30 बजे तक चला। सभी शिक्षक, विद्यार्थियों के साथ विद्यालय परिसर में आने वाले प्रत्येक आगंतुक से भी अपेक्षा की गई कि सभी मौन रहकर ही अपने सारे काम करें। इसका उद्देश्य मौन रहकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि देना था।

विद्यालय की प्राचार्य वीणा वाजपेयी ने बताया कि विद्यालय की इस अनूठी परंपरा को शुरू करने का श्रेय स्व. रामेश्वर प्रसाद गुरु पूर्व महापौर के साथ ही विद्यालय के स्वर्णिम युग के प्राचार्य स्व.एसपी निगम को जाता है। जिसकी शुरुआत 61 वर्ष पहले की गई थी। खास बात यह है कि परंपराएं बन तो जाती हैं लेकिन उन्हें निभाना कठिन हो जाता है लेकिन मॉडल स्कूल में मौन क यह परंपरा अनवरत चली आ रही है विद्यालय प्रशासन हर हाल में 30 जनव को होने वाले मौन का पालन करता है।

विद्यालय में अभी नवमीं से 12व तक के विद्यार्थी पहुंच रहे हैं जिनक संख्या काफी कम है। जब विद्यालय विद्यार्थियों की पूरी संख्या होती है जो कि लगभग तीन हजार होगी, तब भी यह मौ पूरी तरह सफलता से आयोजित होता है इतने वर्षों से विद्यालय में अध्ययन कर हुए विद्यार्थी भी 30 जनवरी पर मौन रख के अभ्यस्थ हो चुके हैं। उन्हें पता है कि यह मौन रखकर हम बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्टाफ का कहना है कि वैसे त हम हर समय बातचीत करते ही रह हैं। राष्ट्रपिता के स्मरण में कुछ घंटे मौ रहकर हम उन्हें याद करते हैं।

मौन के बावजूद विद्यालय में पढ़ा भी हुई और अन्य प्रबंधन संबंधित स काम भी। मौन की समाप्ति के बाद ठीक एक बजकर 30 मिनट पर रामधुन व बा के भजनों के साथ मौन व्रत का समाप किया गया।

मॉडल स्कूल में मौन रखकर अध्ययन-अध्यापन करते विद्यार्थी। ● **नईदुनिया**

समाज में सभी को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से बनाई फिल्म 'मास्साब'

सतना के युवा निर्माता–अभिनेता शिवा के प्रयास की हो रही तारीफ

पीपुल्स संवाददाता ● सतना

editor@peoplessamachar.co.in

युवा अभिनेता शिवा सूर्यवंशी फिल्म 'मास्साब' में अपने अभिनय के लिए देश-विदेश से तारीफ और पुरस्कार से बहुत उत्साहित हैं। इस बात से उनकी खुशी दुगनी हो गयी जब इस सप्ताह रिलीज हुयी फिल्म 'मास्साब' सतना में विराटनगर स्थित पीवीआर में प्रदर्शित हो रही है।

दरअसल फिल्म मास्साब की निर्मात्री रोहिणी एलबी सिंह का सतना के निकट नयागांव में मायका है और शिवा सूर्यवंशी का ननिहाल है। शिवा अपने नानाजी के यहां से काफी भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं, लिहाजा सतना शहर के साथ उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब उनकी फिल्म और अभिनय की तारीफ पुरी दुनिया में हो रही है और फिल्म सतना में प्रदर्शित हो रही है, तो यह उनके लिए खुशी और गर्व के क्षण हैं।

राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में मिले पुरस्कार

शिवा न सिर्फ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में ढेरों पुरस्कारों और प्रशंसा जीतने के बाद अब फिल्म इस सप्ताह सिनेमागृहों में रिलीज हुई है। इस फिल्म से अपने कैरियर की शुरूआत करने जा रहे शिवा 'मास्साब ' में मुख्य नायक के तौर पर नजर आ रहे हैं। वे फिल्म में एक आदर्श शिक्षक आशीष कुमार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य है समाज में सभी को शिक्षा मिले। फिल्म की मुख्य नायिका शीतल सिंह हैं, बाकी कलाकारों में कृतिका सिंह, चंद्रभूषण, नर्मदेश्वर दुबे, शरदराज, संजना शर्मा, हरीश मौर्या, हुसैन खान, बृजेश्वर, जय प्रकाश आदि नजर आएंगे।

पौधों की क्यारी से लेकर दीवारों पर प्रेरणादायक नारे की सुंदर चित्रकारी आकर्षण का केंद्र बनी

सुनवाहा का हाई स्कूल स्वच्छता और सुंदरता में अव्वल

पीपुल्स संवाददाता ● सुल्तानगंज
मो.नं. 6265666845

कस्बा से 18 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल में बना सुनवाहा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों लोगों को आकर्षण एवं प्रेरणा का केंद्र बना है। संस्था प्राचार्य अजय दुबे की लगन ने स्कूल परिसर को हरा-भरा, स्वच्छ एवं सुंदर बना दिया है, परिसर में लगे पौधों की क्यारी से लेकर दीवारों तक प्रेरणादायक नारे सुंदर चित्रकारी आदि से सजाया गया है।

स्वच्छ एवं सुंदर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का परिसर।

स्वच्छभारत अभियान

प्राचार्य अजय दुबे ने बताया महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने 'स्वच्छ भारत' का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी।

स्वच्छ एवं सुंदर विद्यालय अभियान पहल

सुनवाहा शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य अजय दुबे ने बताया सरकार की मंशा अनुसार इस बार उच्च अधिकारियों के निर्देशन में प्रत्येक विद्यालय को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे जिसके तहत विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए मरम्मत, पुताई, लेखन, पौधरोपण किया जा रहा हैं, विद्यालय बच्चों के संस्कारो के सृजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अकथ प्रयास करना चाहिए, स्वच्छ एवं सुंदर जगह पर बच्चों के मन में सुंदर विचार एवं सुंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चों में देश भक्ति स्वच्छ संस्कार डालना शिक्षकों की महत्वपूर्ण जवाबदारी है।

स्कूल परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जनपद सदस्य जयपाल सिंह ठाकुर, पुष्पेंद्र ठाकुर, डॉक्टर बालाप्रसाद लोधी, संदीप ठाकुर आदि लोगों ने इस कार्य की सराहना की है।

पथरिया में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग

स्थानीय लोगों का मिल रहा है समर्थन

पीपुल्स संवाददाता ● पथरिया
मो.नं. 7974091940

केंद्रीय विद्यालय को पथरिया में खोलने की मांग नगर के लोगों ने प्रारंभ का दी है। ज्ञातव्य हो कि 2017-18 में तत्कालीन विधायक लखन पटेल के द्वारा उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावेड़कर से मुलाकात कर पथरिया मे उपलब्ध संसाधनों, दस्तावेजों की फाइल भी सौंपी थी।

जिला दमोह के तत्कालीन कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने भी जिसके लिए प्रयास किए थे। केंद्रीय विद्यालय से संबंधित फाइल केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भी भेजने की बात सामने आई थी। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर पथरिया में केंद्रीय विद्यालय की मांग को उठाने के लिए फिर प्रयास नहीं हुए। दमोह और हटा के बाद पथरिया, जिले का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला क्षेत्र हैं। पथरिया की भौगोलिक स्थिति सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहां रेलमार्ग व सड़क मार्ग दोनों से आवागमन की सुविधा उपलब्ध हैं। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय पर पथरिया का हक जायज हैं। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय न होने के कारण पथरिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे दमोह और सागर बस और अन्य साधनों से रोजाना अप - डाउन करते हैं, जिससे अभिभावक चिंतित रहते हैं।

सर्वे हो चुका है

केंद्रीय विद्यालय का सर्वे हो चुका है। नए भवन का निर्माण नहीं होता तब तक मॉडल स्कूल में प्रारंभ करने का सुझाव मेरे द्वारा दिया गया।

-लखन पटेल, पूर्व विधायक, पथरिया

मांग उठना सामान्य बात है

अगर दमोह के लिए प्रहलाद सिंह पटेल जैसा केंद्रीय मंत्री और सांसद मिला है तो केंद्रीय विद्यालय की मांग उठना सामान्य सी बात है।

-अभिषेक रामा साहू, युवा

शैक्षणिक माहौल बनेगा

केंद्रीय विद्यालय लाने के लिए पूर्व विधायक लखन पटेल ने अपने कार्यकाल में अच्छे प्रयास किए थे। क्षेत्र में अच्छा शैक्षणिक माहौल विकसित होगा।

-अंकित पटेल

नई शिक्षा नीति जायज है

जब नई शिक्षा नीति और अन्य नवाचार की बाते सामने आती रहती है, तो केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधा इस तहसील को देना भी जायज है।

-शांतुन सोनी, समाजसेवी

सहायक संचालक ने स्कूलों का किया निरीक्षण, छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ उदयपुरा

सहायक संचालक एवं जिले की प्रभारी अंजना मिश्रा एवं एडीपीसी निधि शर्मा द्वारा ब्लॉक के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। सुबह से शाम तक उन्होंने 5 विद्यालय की व्यवस्थाएं देखी। उत्कृष्ट विद्यालय उदयपुरा एवं कन्या शाला उदयपुरा हाई स्कूल कुछवाड़ा एवं हाई स्कूल नूर नगर एवं हाई स्कूल बौरास का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय उदयपुरा और कन्या शाला की व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने हाई स्कूल नूर नगर का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाएं सुधारने और छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावां हाई स्कूल कुछवाड़ा में भी विद्यालय संचालित था अंत में टीम द्वारा उत्कृष्ट स्कूल में प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया।

उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत बनने वाली प्रयोगशालाओं को भी देखा। प्राचार्य एसपी मिश्रा ने बताया कि विद्यालय की व्यवस्था से निरीक्षण दल पूर्ण संतुष्ट दिखाई दिया। उन्होंने प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों से चर्चा की। कन्या शाला के प्राचार्य राजेश कौरव ने बताया कि विद्यालय में आज काफी अच्छी उपस्थिति रही। उत्कृष्ट विद्यालय में 328 छात्र उपस्थित थे, वही कन्या शाला में 310 छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा दोनों विद्यालय पूरी तरह संचालित था शाम 4 बजे निरीक्षण दल द्वारा हाई स्कूल बोरास का निरीक्षण किया।

सरस्वती शिशु मंदिर छपारा विद्यालय में जिला प्राचार्य, आचार्य व समिति बैठक

हरिभूमि न्यूज। छपारा।

सरस्वती शिक्षा परिषद महाकोशल प्रान्त द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय छपारा में जिला स्तरीय प्राचार्य,आचार्य और संयोजक मंडल की सामूहिक बैठक आयोजित की गई जिसमें नगरीय विद्यालय और ग्राम भरती विद्यालय केप्राचार्य,प्रधानाचार्य,आचार्य,आचार्यो व समिति पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर मातृ वंदना की गई। कार्यक्रम में डॉ आनंद राव संगठन मंत्री, इंदल पटेल,अरुण पटेवार का स्वागत साल श्रीफल के माध्यम से शैलेन्द्र चौरसिया व्यवस्थापक द्वारा किया गया अतिथियों का परिचय

चुन्नीलाल बोपचे विभाग समन्वयक द्वारा कराया गया माननीय संगठन मंत्री द्वारा निर्धारित चार विन्दुओं की समीक्षा कर सभी को आगामी लक्ष्य देते हुए मर्दर्शन प्रदान किये। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन जीतेन्द्र कुमार सोनी प्राचार्य द्वारा किया गया। इस बैठक में भास्कर क्षेत्रीय क्रीडा प्रमुख राजेन्द्र जैन जिला समन्वयक आदि की उपस्थिति रही।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रशिक्षण कायर्शाला का आयोजन

शासन द्वारा लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक बैठक का आयोजन शनिवार 30 जनवरी को सरस्वती शिशु मंदिर में किया जाना है। शनिवार सुबह 9 बजे से विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्मुखीकरण विभागीय कायर्शाला सिवनी और छिंदवाड़ा के समस्त प्राचार्य आचार्य 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीआरसी छपारा के द्वारा किया जाना है। इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षा नीति में हुए नए परिवर्तन के विषय में कायर्शाला का आयोजन किया जाना है।

10 साल बाद खुली फाइल • 2008 से 2018-19 तक अतिरिक्त कक्ष, किचन शेड के पैसे हजम

सरपंच-सचिवों ने स्कूलों में 143 कामों के 4.9 करोड़ दबाए, अब होगी वसूली

भास्कर संवाददाता | गुना

2008 से 2018-19 के बीच शिक्षा विभाग में मंजूर हुए 143 कामों के लिए 4.9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए लेकिन मौके पर कोई निर्माण नहीं हुआ। अब 10 साल बाद इन घोटालों की फाइल खुल रही है। इसके जिम्मेदार सरपंच व सचिवों से ब्याज सहित पैसे वसूले जाएंगे। अगर वे आनाकानी करेंगे तो उनकी कुर्की होगी।

एक माह की मोहलत

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि सरकारी सिस्टम में काम कर रहे यह लोग निर्माण माफिया की तरह हैं। इन सभी को वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं। इसमें उन्हें एक माह का वक्त दिया जाएगा। अगर इस दौरान उन्होंने राशि जमा न की तो एक साथ कई कार्रवाई की जाएंगी। इसमें कुर्की, एफआईआर के साथ उनका नाम अखबारों में प्रकाशित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई सरपंचों पर इन मामलों को लेकर धारा 40 की कार्रवाई चल रही है। वहीं इसमें दोषी पाए जाने वाले सचिवों को सरकारी नियम के तहत जवाबदेही के दायरे में लाया जाएगा।

दोबारा ऐसा न हो इसलिए रुपए देने में आनाकानी की तो कुर्की भी करेंगे

जिम्मेदार बड़े अफसर भी, उनसे भी हो सवाल

1. सरपंच एवं सचिव : जिस समय का यह घपला है तब स्कूलों में होने वाले निर्माण कार्यों की राशि पंचायतों में आती थी। उक्त राशि निकालने के लिए सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर होना जरूरी हैं।

2. शिक्षा विभाग : सर्वशिक्षा अभियान के तहत होने वाले कामों की निगरानी डीपीसी यानि जिला परियोजना समन्वयक के यहां से होती है। विभाग के अपने इंजीनियर इस काम को करवाते हैं। इनमें से किसी ने भी काम की प्रगति को नहीं देखा।

3. इस कार्यकाल के दौरान रहे जिला पंचायत सीईओ भी जवाबदेह हैं। सारा पैसा उनके कार्यालय से होकर ही पंचायतों तक पहुंचता है। वे समय-समय पर समीक्षा भी करते हैं। ऐसे में उन्होंने इतना बड़ा घपला कैसे नजरअंदाज कर दिया, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए।

4 साल पहले भी खुली थी फाइलें

करीब 4 साल पहले भी शिक्षा विभाग में हुए इस घोटाले की फाइल खुल चुकी है। तत्कालीन अपर कलेक्टर नियाज अहमद खां को जब जिला पंचायत सीईओ का अतिरिक्त प्रभार मिला, तब उन्होंने स्कूल निर्माण के नाम 1.75 करोड़ रुपए निकालकर डकार चुके 125 सरपंचों की फाइलें खोली थीं। यह मामले भी 8 साल पुराने थे। हालांकि बाद में यह मामला रफा-दफा हो गया। इस बार कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा हम सभी से एक-एक पाई वसूल कर लेंगे।

सरपंचों को ही स्कूलों में काम कराने का वित्तीय अधिकार था

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी डीपीसी सोनम जैन ने बताया कि इनमें से ज्यादातर राशि अतिरिक्त कक्ष के लिए मंजूर की गई थी। मौके पर जाकर देखा तो यह काम किया ही नहीं गया। इसके अलावा किचन शेड, बाउंड्रीवॉल जैसे कामों के लिए राशि मंजूर की गई थी। लेकिन ये काम भी कहीं नहीं दिखा। तब सरपंचों को ही स्कूलों में काम कराने का वित्तीय अधिकार था। इसलिए यह घोटाला हो गया।

... अब सावधानी

शिक्षक पालक संघों को कहा- इंजीनियर पैसे मांगे तो वाट्स एप से सूचना दें

स्कूलों लंबे अरसे बाद बड़े पैमाने पर काम होने हैं। इनमें 300 शौचालयों का निर्माण अहम होगा। कलेक्टर ने कहा कि यह काम शाला प्रबंध समिति के माध्यम से होगा। इसमें पालकों व शिक्षकों की भागीदारी रहती है। उन्होंने कहा कि समितियों से गया है कि वे इंजीनियरों को एक भी पैसा न दें। अगर कोई काम में आनाकानी करे तो उसकी सूचना उन्हें मोबाइल पर दें। वहीं शिक्षा विभाग के सभी असिस्टेंट इंजीनियरों को भी यह चेतावनी दी गई है कि अगर 31 मार्च तक काम पूरा नहीं हुआ तो उनकी संविदा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

भास्कर

सम्मान समारोह में छात्रा को किया सम्मानित, बोर्ड परीक्षा में किया था स्कूल का नाम रोशन

अशोकनगर | शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर की छात्रा ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर अंक अर्जित कर विद्यालय और जिला अशोकनगर का नाम किया था। जिसे देखते हुए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित किया था जिसके तहत छात्रा को सम्मानित किया गया। छात्रा कुलसुम ने सभी विषयों में डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए थे। जहां छात्रा ने विद्यालय में पढ़कर ही उच्चतम अंक प्राप्त किए। राज्यमंत्री, कलेक्टर, डीईओ व विधायक ने छात्रा को 5 हजार का चेक और स्मृति चिह्न भेंट किया था। इस दौरान विद्यालय प्राचार्य जयआनंद जोशी,

अभिषेक चौधरी, राजू लाड़, अनुप्रिया श्रीवास्तव, नेहा शर्मा, शीतल तोमर मौजूद रहे।

भास्कर

सीबीएसई से जुड़े स्कूलों और केवी ने वार्षिक परीक्षा का तैयार किया शेड्यूल

कक्षा 8वीं तक की परीक्षाएं ऑनलाइन कराएंगे स्कूल, 9वीं और 11वीं की होंगी ऑफलाइन

कोविड-19 बदलाव

सिटी रिपोर्टर | केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड-19 को देखते हुए इस बार परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर होगी। वहीं शहर के सीबीएसई से जुड़े स्कूल 8वीं तक ऑनलाइन और शेष कक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन कराएंगे।

फरवरी में होंगी सीबीएसई स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) से मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। इसमें छात्रों को कैमरे के सामने ही परीक्षा देनी होगी। इसके लिए स्कूलों ने अभी से मॉनिटरिंग के लिए स्कूल टीचर्स को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। वहीं कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं स्कूलों में ही ऑफलाइन होंगी। इसके लिए छात्रों को स्कूल आना होगा और 3 घंटे की परीक्षा देनी होगी। अधिकतर स्कूलों में फरवरी के दूसरे सप्ताह से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो 15 मार्च तक पूरी करा ली जाएंगी। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च में होने की वजह से स्कूलों में फरवरी में रेमेडियल क्लासेस और एक्सट्रा क्लासेस का आयोजन किया जाएगा। इसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

• ऑनलाइन एक्जाम मॉनिटरिंग का प्रशिक्षण लेती टीचर।

ऑनलाइन के लिए यह बनाएं नियम

- ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की पहले उपस्थिति दर्ज की जाएगी। साथ ही निर्देश रहेंगे कि परीक्षा के दौरान मोबाइल का कैमरा बंद नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई छात्र स्कूल से ऑनलाइन कनेक्ट नहीं होता है। तो उसे परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा।
- प्रैक्टीकल के रूप में प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद अभिभावकों को स्कूल में जमा करने होंगे।
- पेपर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे।
- अभिभावकों को सीलबंद लिफाफे में ही विद्यार्थियों की आंसरशीट को स्कूल में जमा करनी होगी।

केवी की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से

केंद्रीय विद्यालयों में टर्म एंड एग्जाम 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके हिसाब से केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा तीसरी से 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से 20 मार्च तक होंगी। परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में होंगी। ऑफलाइन परीक्षा में सिर्फ वे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। शेष सभी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे।

क्लास के मुताबिक रहेगी समयावधि

- **कक्षा 3 से 5वीं तक:** इसमें कुल 40 अंकों का पेपर होगा। प्रश्नपत्र में मल्टीपल च्वाइस, डिस्क्रिप्टिव और मौखिक सवाल होंगे। इसमें 10 अंकों के एमसीक्यू, 15 अंकों के डिस्क्रिप्टिव और शेष मौखिक सवाल पूछे जाएंगे।
- **परीक्षा अवधि-** यह 1 घंटे की होगी।
- **कक्षा 6वीं से 8वीं तक:** इसमें कुल 80 अंकों का पेपर होगा। इसमें 25 अंकों के मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस, 40 के डिस्क्रिप्टिव और 15 अंकों को मौखिक सवाल होंगे।
- **परीक्षा अवधि-** यह परीक्षा 2 घंटे की होगी।
- **कक्षा 9वीं और 11वीं तक:** इसमें कुल 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे।
- **परीक्षा अवधि:** यह परीक्षा 3 घंटे की होगी।

भास्कर

मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया फिर संविधान पालन की दिलाई गई शपथ

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम

भास्कर संवाददाता | भिंड

मां बीजासेन शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति भिंड द्वारा एमबीएस एज्यूकेशन अकादमी अटेर रोड में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अकादमी डॉयरेक्टर रामोतार शिवहरे ने मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही छात्रों को उन्होंने संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान डॉयरेक्टर शिवहरे ने कहा कि वर्ष 1950 को हमारे देश का संविधान गठित हुआ था, उस दिन हम पूरी तरह से स्वतंत्र हुए थे। भारत विविध धर्मों, आस्थाओं और संस्कृतियों का देश है और यहां हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। हर धर्म को मानने वाले लोग पूरे उल्लास के साथ अपने पर्व मनाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे भी हैं, जो प्रत्येक देशवासी के लिए महत्वपूर्ण हैं और पूरे देश में सम्मान और स्नेह के साथ मनाए जाते हैं। 26 जनवरी भी एक ऐसा ही दिन है, जो देश का राष्ट्रीय पर्व है। इस मौके पर अनुराग शिवहरे मौजूद रहे।

अकादमी के मेधावी छात्र, जिनका सम्मान किया गया।

पेंशनर्स एसोसिएशन की याचिका पर मांगा जवाब

जबलपुर. हाईकोर्ट ने पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया। पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी व जिला अध्यक्ष एचपी उरमलिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी अग्रवाल व संजय अग्रवाल ने तर्कदिया कि राज्य के पांच लाख पेंशनर्स राज्य शासन से सातवें वेतन आयोग के 27 माह के एरियर्स के तलबगार हैं। कई बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

आईआईएसईआर • डिप्रेशन से निजात पाने के लिए छात्र अब चेन्नई के मेडिटेशन सेंटर में करा रहा इलाज

पीएचडी के लिए चार साल से ज्यादा की रिसर्च, गाडड ने संस्थान छोड़ा, नए गाइड का विषय अलग होने से डिप्रेशन में आया छात्र

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) के एक पीएचचडी स्कालर के रिसर्च के दौरान बीच में ही गाइड के संस्थान छोड़ने की वजह से एक छात्र डिप्रेशन में है। संस्थान की ओर से जो नया गाइड मिला है, उनकी विशेषज्ञता अलग क्षेत्र में है। इस वजह से छात्र और गाइड के बीच पटरी नहीं बैठी। कैरियर और मेहनत बर्बाद होती देख छात्र अब वह चेन्नई में डिप्रेशन दूर करने के लिए मेडिटेशन सेंटर में हैं। आईसर के पीएचडी स्कालर लोकनाथ कुंडू 2016 से पीएचडी छात्र हैं। वे सीएसआईआर फैलो भी रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने जरूरी कोर्स वर्क व अन्य जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थी। यहां वे डॉ. रोमी बैनर्जी के सुपरविजन में पीएचडी कर रहे थे।

कोरोनाकाल में सुपरवाइजर ने नहीं किया सपोर्ट, एचओडी ने नहीं निकाला हल

कुंडू को जुलाई 2019 में यह पता चला कि डॉ. बैनर्जी ने संस्थान छोड़ दिया है। उन्होंने संस्थान से एनओसी भी ले ली। उन्होंने डॉ. बैनर्जी के मार्गदर्शन में तीन साल तक पीएचडी के लिए रिसर्च किया था। कुंडू ने बताया कि उन्हें आईसर के मैथामेटिक्स विभाग ने कहा कि वे विषय परिवर्तन कर लें। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद डॉ. सिद्धार्थ सरकार को गाइड बना दिया गया। कुंडू ने बताया कि डॉ. सरकार की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी। ऐसे में वे काम के लिए समय मांग रहे थे। ऐसे में विषय अलग होने से दिक्कतें होना शुरू हुईं। कुंडू ने आरोप लगाया कि उन्हें हताश किया जाने लगा। कोरोना के समय वे घर आ गए और रिसर्च करते रहे पर सुपरवाइजर ने कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बताया कि उन्हें फेल किया जाने लगा। इस वजह से वे डिप्रेशन में आ गए। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने एचओडी से भी बात की थी पर कोई हल नहीं निकला। वे गाइड बदलने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी चार साल से ज्यादा मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है।

कुंडू ने बताया कि लगातार पिछड़ने की वजह से उनका पीएचडी से टर्मिनेशन हो सकता है। कुंडू ने आरोप लगाया है कि वे एकेडमिक पालिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। इधर, संस्थान का कहना है कि प्रबंधन छात्रों के लिए है। सब चाहते हैं कि छात्र की पीएचडी पूरी हो।

को-गाइड लेने को तैयार नहीं है छात्र, जल्द हल करेंगे यह समस्या

यह केस हमारी जानकारी में है। गाडड और छात्र का विषय भिन्न होने से उसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हम उसे को-गाइड देने को तैयार हैं। लेकिन, छात्र ही इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। कह रहा है कि वह खुद ही बिना गाडड के रिसर्च करेगा। हम लोग जल्द ही इस समस्या को दूर करेंगे और कोई हल निकालेंगे। कोई नहीं चाहता है कि किसी की मेहनत बर्बाद हो, पूरा सहयोग करेंगे।

डॉ. सत्यमूर्ति, रजिस्ट्रार, आईसर

सरकार का प्रयास विफलः रोजगार का पंजीयन बेकार, प्रदेश के आवेदक परेशान

मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों के एक लाख युवा शामिल

मेरा भविष्य

ग्वालियर • डीबी स्टार

एमपी पीएससी, पीईबी सहित अन्य परीक्षाओं के लिए अभी तक आठ लाख से अधिक आवेदकों ने ऑनलाइन फार्म भरे हैं इनमें एक लाख से अधिक आवेदक बाहरी राज्यों के हैं। मप्र में निवास नहीं करने वाले इन आवेदकों ने उन्होंने रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करा कर परीक्षा फॉर्म भर दिया है। ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों के आवेदकों से मप्र के आवेदकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जबकि मप्र सरकार ने प्रदेश के युवाओं को अवसर देने के लिए ही मप्र का रोजगार पंजीयन आवश्यक किया था।

मप्र सरकार ने बाहरी राज्यों के आवेदकों को मध्य प्रदेश की परीक्षाओं से बाहर रखने के लिए रोजगार पंजीयन का नियम लागू किया लेकिन रोजगार पंजीयन में मार्कशीट, मूल निवासी व अन्य जानकारियां न मांगे जाने के कारण बाहरी राज्यों के आवेदक आराम से देश के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन रोजगार पंजीयन करा रहे हैं। इसका सीधा नुकसान मप्र के मूल निवासियों को हो रहा है। ऐसे में रोजगार पंजीयन का नियम केवल दिखावा साबित हो रहा है और दूसरे राज्यों के कारण मप्र के मूल निवासियों को अपने ही प्रदेश में नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है।

सांकेतिक

रोक का प्रावधान ही नहीं

रोजगार पंजीयन पोर्टल पर रोक का कोई प्रावधान नहीं है। पंजीयन के लिए मप्र का मूल निवासी होने का प्रावधान नहीं होने से यह दिक्कत बनी हुई है। यही वजह है कि अन्य प्रदेश के बेरोजगार पोर्टल पर आसानी से पंजीयन करा रहे हैं।

नौकरियों में भी आ गए

रोजगार पोर्टल पर पंजीयन वर्ष 2017 में लागू किया गया था। उसके बाद से पंजीयन में संशोधन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गई। इस दौरान बाहरी प्रदेश के कई आवेदक यहां की नौकरियों पर ज्वॉइन कर चुके हैं।

आरक्षक भर्ती की तारीख बढ़ाई

रोजगार कार्यालय की वेबसाइट में पंजीयन कराने के दौरान आई समस्या के कारण पीईबी ने आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 30 जनवरी से बढ़ाकर छह फरवरी कर दी है। इस परीक्षा में दस लाख से अधिक आवेदक शामिल होने की संभावना है। पंजीयन के लिए आवेदकों की भीड़ के कारण साइट बार बार बंद हो रही थी।

विधान सभा में भी उठ चुका है मुद्दा

यह मामला मप्र की विधानसभा में उठ चुका है। जुलाई 2019 में विधानसभा में विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने बाहरी राज्यों की उम्र सीमा में छूट पर सवाल उठाया था। इस संबंध में तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा था कि हम नए नियम बना रहे है जिसमें रोजगार पंजीयन कराना जरूरी कर दिया गया है जिससे रोजगार पंजीयन प्रदेश के युवा ही करा सकते हैं।

अब सुनें अफसरों की बात

रोजगार पंजीयन के मामले में अभी स्वीकृति नहीं मिली है

रोजगार पंजीयन में मप्र के निवासियों को ही शामिल किए जाने के निर्णय पर अभी शासन स्तर पर स्वीकृति नहीं मिली है। इस कारण इस पर अभी अमल शुरू नहीं हो पाया है। हमें जब भी स्वीकृति मिलेगी, तब नए आदेश जारी किए जाएंगे।

श्रीनिवास शर्मा, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

हमें पता नहीं चल पाता आवेदक के राज्य का नाम

मध्यप्रदेश में ऑनलाइन रोजगार पंजीयन कराने के लिए रोजगार पोर्टल पर सिर्फ आवेदक का नाम, आधार नंबर और शहर का नाम पूछा जाता है। इस कारण हमें पता नहीं चल पाता कि किस राज्य का आवेदक रोजगार पंजीयन करा रहा है।

षणमुख प्रिया मिश्रा, आयुक्त रोजगार

हमारे साथ धोखा है, सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए

मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। रोजगार पंजीयन की व्यवस्था इस लिए की गई थी कि प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी का अवसर मिल सके लेकिन रोजगार पोर्टल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे अन्य राज्यों के आवेदक मप्र मे पंजीयन न करा सके। इसी कारण सभी राज्यों के आवेदक मप्र का पंजीयन करा कर परीक्षा में शामिल हो रहे है तथा नौकरी भी कर रहे है।

कुबेर राजपूत, शिकायतकर्ता

अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही महाविद्यालय में पढ़ाई

जिम्मेदारों की अनदेखी से अध्यापन में असर

हरिभूमि न्यूज, बरही

बरही में संचालित शासकीय महाविद्यालय शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य अतिथियों शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। महाविद्यालय में मात्र 3 नियमित शिक्षक है। 12 अतिथि विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जो नाकाफी है। अनुमान लगाया जाए तो शिक्षकों के खाते में 11 से 14 कक्षाओं का भार रहता है। छात्रों का भविष्य भगवान भरोसे चल रहा है इस ओर किसी का ध्यान नही है। छात्रों के अपेक्षा छात्रायें की संख्या कई गुना अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों से बरही महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने छात्र-छात्राएं आती हैं। शिक्षकों की कमी व क्लास रूम न होने से शिक्षा ग्रहण नही कर पा रही हैं। प्राचार्य वर्मा ने बताया इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर चुका हूं। महाविद्यालय की समस्या से अवगत करा दिया हूं पर आज दिनांक तक महाविद्यालय के प्रति शासन प्रशासन द्वारा कोई अमल नही किया गया। मैंने अपनी पूरी मेहनत से महाविद्यालय के प्रति सहयोग करता हूं जो मेरा दायित्व है। बरही महाविद्यालय कई समस्याओं से जूझ रहा है इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।

2 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत

शासकीय महाविद्यालय बरही में कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया निरन्तर विकास की ओर अग्रसर है। विगत वर्ष जिस महाविद्यालय में 400 छात्र-छात्रायें कला संकाय से अध्यनरत थे। आज उस महाविद्यालय में 2000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं विज्ञान राजनीति इतिहास आदि विषयों में स्नाकोत्तर की उपाधि भी महाविद्यालय से प्राप्त कर रहे है संपूर्ण श्रेय निश्चय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोगियों को है जिसका परितोषिक के रुप इस महाविद्यालय को 2019-2020में जबलपुर संभाग में बी-ग्रेड प्राप्त हुआ है

बीयू में लागू होगा स्टूडेंट चार्टर, छात्रों की समस्या समय पर हल नहीं होने पर सजा का भी प्रावधान

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में डेढ़ दर्जन मुद्दों पर चर्चा

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में स्टूडेंट्स की 26 तरह की समस्याओं को समय सीमा में हल करने के लिए स्टूडेंट चार्टर लागू करने की तैयारी है।

बीयू की शनिवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में इस पर चर्चा हुई। ईसी की बैठक में लगभग डेढ़ दर्जन अन्य प्रस्ताव रखे गए, जिन पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। ज्ञात हो कि ईसी मेंबर किशन सूर्यवंशी ने पिछली बैठक में स्टूडेंट चार्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि उसमें समय सीमा में छात्रों की समस्या हल नहीं होने पर अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सजा का प्रावधान नहीं होने से इसे संशोधित कर अगली बैठक में रखने को कहा गया है। इसमें छात्रों से जुड़ी 26

प्रकार की सुविधाएं चिह्नित की गई हैं। बैठक में 11 साल पुराने केबल के 3 लाख 90 हजार रुपए के भुगतान का प्रस्ताव रखा गया। इसकी ओरिजनल फाइल के बजाय फोटोकॉपी पेश करने के कारण ईसी ने कुलपति को अधिकृत किया है कि इसका अध्ययन कर अगली बैठक में रखें। बीयू द्वारा पूर्व में 12 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा करने का मामला भी बैठक में रखा गया, जिसमें ईसी ने कंसल्टेंट रखे जाने का आदेश दिया, ताकि इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी न हो।

अब 65 के बजाय 62 वर्ष में रिटायर होंगी प्रो. शुक्ला

अंबेडकर विवि की कुलपति प्रो. आशा शुक्ला को छानबीन समिति ने प्रोफेसर के बजाय परियोजना अधिकारी बताया है। इस पर ईसी ने भी मुहर लगा दी। अब वह 65 के बजाय 62 वर्ष में रिटायर होंगी। हालांकि कुलपति पद पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रो. शुक्ला कुलपति बनने से पूर्व बीयू के महिला अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष थीं। उनके प्रोफेसर होने पर विवाद था।

प्लेसमेंट सेल बनेगी: ईसी में प्लेसमेंट अधिकारी नरेन्द्र रघुवंशी की 25 हजार से 35 हजार रुपए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। ईसी ने सहमति दे दी। बीयू में पिछले वर्षों में छात्रों का कोई खास प्लेसमेंट नहीं होने पर ईसी ने प्लेसमेंट सेल बनाने के निर्देश दिए।

कॉलेज खुले, सरकारी हॉस्टल बंद, छात्र किराए के कमरों व निजी छात्रावासों में रहने को मजबूर

कोरोना कमजोर: तैयारियां पूरी, शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार, बजट से बाहर जा रहा बाहर रहना

नेहा जैन ● इंदौर
मो.नं. 9993777268

इंदौर में कोरोना संक्रमण का प्रसार कमजोर पड़ गया है। फलस्वरूप शासन के आदेश के बाद शहर में सभी कॉलेज पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स सरकारी हॉस्टलों को खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं। कारण, इन्हें खोलने के लिए सरकार से अनुमित का न मिलना। इससे छात्र प्राइवेट हॉस्टल या किराए से कमरा लेकर रहने को मजबूर हैं। ज्ञात हो कि मध्य भारत का एजुकेशन हब होने से इंदौर में प्रदेश और बाहर से आने वालों की संख्या अधिक है। अधिकतर छात्र सरकारी हॉस्टल में रहने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बजट में होते हैं। इंदौर में 19 सरकारी हॉस्टल हैं। इनमें डीएवीवी के यूटीडी कैंपस में 2500 स्टूडेंट्स की क्षमता वाले 14 हॉस्टल हैं। चार सरकारी जीजाबाई, होल्कर साइंस, जीडीसी, सीएसीसी तथा एक आदिम जाति कल्याण विभाग का हॉस्टल है, जो 22 मार्च 2020 से बंद पड़े हैं।

सरकारी हॉस्टल का किराया कम- सरकारी कॉलेज से पीएचडी कर रहीं बड़वाह निवासी दुर्गा बताती हैं कि लॉकडाउन के पहले तक डीएवीवी के सरकारी हॉस्टल में रह रही थी। एक जनवरी से फिर इंदौर लौटी हूं, लेकिन किराये के कमरे में रहना पड़ रहा है, जहां महीने का खर्चा पांच हजार से अधिक है।

निजी का खर्चा उठाने में असक्षम, मजबूरी में रहना पड़ रहा

आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से एमएसडब्ल्यू कर रहे छात्र लोकेंद्र भौसले बताते हैं वे आदिम जाति एवं कल्याण विभाग के हॉस्टल में तीन साल से रहे हैं, पर अब किराए से कमरा लिया है। एक महीने का किराया चार हजार से अधिक है, जबकि सरकारी हॉस्टल निःशुल्क था। लोकेंद्र आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं। वे बताते हैं कि हॉस्टल में ही मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज छूट गए हैं। इससे एडमिशन और अन्य परीक्षा फार्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। हॉस्टल खुलने से दस्तावेज मिल सकेंगे।

शासन के आदेश का इंतजार

डीएवीवी के यूटीडी हॉस्टल के वीफ वार्डन प्रो. जीएल प्रजापति के अनुसार, कॉलेज खुलने के बाद स्टूडेंट्स के कॉल की संख्या बढ़ गई है। रोज 50-60 से अधिक कॉल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, जो हॉस्टल खुलने की जानकारी मांग रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। शासन के आदेश मिलते ही हॉस्टल खोल दिये जाएंगे।

रेट बढ़ाए- युकां नेता जावेद खान, छात्र नेता विवेक सोनी, अभिनव हार्डिया ने बताया बाहरी छात्र 5 से 11 हजार के प्रति माह के खर्चे पर निजी हॉस्टल आदि में रहने को मजबूर है। निजी हॉस्टल वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं।

जीवाजी विवि में पैरामेडिकल और डीफार्मा कोर्स शुरू होंगे

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर
editor@peoplessamachar.co.in

विद्या संबंधी योजना व मूल्यांकन बोर्ड और विद्या परिषद की बैठक हुई

जीवाजी विवि के हेल्थ सेंटर में पैरामेडिकल और फामेर्सी अध्ययनशाला में डिप्लोमा इन फामेर्सी पाठ्यक्रम शुरू होंगे। जाएगा। पाठ्यक्रमों के शुरू होने से विवि की आय में बढ़ोतरी होगी।

वह निर्णय जीवाजी विवि कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को हुई विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की वार्षिक बैठक में लिया गया।बैठक में रेक्टर प्रो. डीडी अग्रवाल, प्रभारी कुलसचिव डॉ. आईके मंसूरी, डॉ. केशव सिंह गुर्जर, प्रो. विवेक बापट, प्रो. पीके तिवारी, प्रो. योगेश उपाध्याय, प्रो. डीसी गुप्ता, प्रो. नलिनी श्रीवास्तव, प्रो.एसके गुप्ता, प्रो. जेएन गौतम, प्रो. एसके शुक्ला, प्रो. केशव ठाकुर मौजूद रहे। दोनों बैठकों

के बाद वर्तमान रेक्टर प्रो डीडी अग्रवाल के रिटायरमेंट होने पर सभी ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें विदाई दी।

ये भी हुए निर्णय

- आजीवन विस्तार शिक्षा व समाजकार्य अध्ययनशाला में स्ववित्तीय स्कीम के अंतर्गत एमए वूमन स्टडीज कोर्स प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
- योग विज्ञान केंद्र अध्ययनशाला तीन वर्षीय 6 सेमेस्टर बीए ऑनर्स योगा सत्र 2021- 2024 से प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त पाठ्यक्रम का संचालन कला संकाय के अंतर्गतहोगा
- प्राणी विज्ञान अध्ययनशाला के अंतर्गत 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्सेस शुरू किए जाएंगे।
- सीआईएफ विभाग के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स एवं सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन सर्टिफिकेट इन एनालिटिकल टेक्निक्स प्रारंभ किए जाने का निर्णय हुआ।
- जेयू की अध्ययनशालाओं में यदि कोई विभाग सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करना चाहता है तो व प्रस्ताव तैयार करे। इसके लिए अनुमति प्रदान करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। मान्यता प्राप्त होने के बाद ही कोर्स को प्रारंभ किया जाएगा।

विद्या परिषद की बैठक में ये निर्णय हुए

कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक विद्या परिषद की बैठक हुई। बैठक में नवीन गठित विद्या संबंधी योजना व मूल्यांकन बोर्ड के लिए तीन विद्वानों प्रो. नागेश्वर राव, कुलपति इंदिरा गांधी मुक्त विवि नई दिल्ली, प्रो. अखिलेश पांडेय कुलपति विक्रम विवि उज्जैन, प्रो. आलोक शर्मा निदेशक आईआईटीटीएम ग्वालियर को मनोनीत किया गया, पीएचडी शोधार्थी छात्रों द्वारा शोध जमा करने की तिथि पहले 31 दिसंबर 2020 तय की गई थी, जिसमें यूजीसी के निदेर्शानुसार बढ़ाकर 30 जून तक करने की सूचना ग्रहण की गई, विदहेल्ड का परीक्षा परिणाम 6 माह के अंदर घोषित किया जाए। इसके बाद भी यदि कोई कठिनाई आती है तो संबंधित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं एवं संबंधित अन्य दस्तावेज परीक्षा परिणाम घोषित होने तक सुरक्षित रखे जाएं। कंप्यूटर सेंटर में पदों को पुनः विज्ञापित कराए जाने के लिए यूजीसी की अर्हता अनुसार कार्यवाही की जाए, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि से तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्ययक्रम उतीर्ण छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी गई, दूरस्थ शिक्षण संस्थान के एमबीए पाठ्यक्रम के लिए अध्यादेश अनुमोदित किया गया, छात्रों एमए से अन्य विषय में एमए व एमएससी से अन्य विषय में एमएससी पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए संबंधित अध्यादेशों के अनुसार कार्यवाही करने की बात हुई।

कोरोना के संकटकाल में अफसरों ने जोखिम उठाकर करवाई है तैयारी

एमपी पीएससी की ऑफलाइन कोचिंग की तैयारी में है सरकार

भदभदा रोड स्थित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में कवायद

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

भोपाल। प्रदेश में पिछड़े और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की पीएससी परीक्षा तैयारी ऑफलाइन करवाने के लिए शासन स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि शासन का आदेश मिलते ही छात्रावास प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बताना होगा कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रतिवर्ष पीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं करवा कर बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करता रहा है। इस विभाग के अधीन चलने वाले राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित कोटा के अनुसार पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के शिक्षित युवा प्रशिक्षण लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते रहे हैं। क्योंकि इस बार घातक कोरो ना की त्रासदी रही है। नतीजतन शासन के आदेश पर अन्य शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ इस छात्रावास को भी बंद कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि शायद विद्यार्थियों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति राज्य सरकार दे सकती है। इस कारण हमारी भी यहां पर पूरी तैयारियां चल रही है। जैसे ही शासनादेश होगा तो तत्काल विद्यार्थियों को छात्रावासों में बुला लिया जाएगा।

अगस्त से लगातार दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण

अधिकारियों का कहना है कि कोरोना में युवाओं की तैयारी का कोई नुकसान ना हो। इस कारण शासन के आदेश पर इन विद्यार्थियों को अगस्त 2020 से ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई थी। 6 माह का यह प्रशिक्षण है जो फरवरी में समाप्त हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में ही विद्यार्थी आकर तैयारी करें, इसके लिए पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। प्रशिक्षण केंद्र के सहायक संचालक अवधेश सिंह सिसोदिया का कहना है कि 20 जनवरी से ऑफलाइन प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। यह प्रशिक्षण 20 मार्च को खत्म होगा।

कोई विद्यार्थी प्रशिक्षण से वंचित ना रहे

रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर एमके गौतम का कहना है कि कोई भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से वंचित न रह जाए, हमारा इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए ऑफलाइन प्रशिक्षण कराने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमने बाकायदा इसका प्रचार भी किया है ताकि प्रशिक्षण लेने वाले पात्र पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उम्मीदवारों तक यह जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा है कि अगर शासन अनुमति देता है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय रोजगार प्रशिक्षण केंद्र में तैयारी का क्रम शुरू किया जाएगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार बनने 21 उम्मीदवारों ने की प्री परीक्षा पास

प्रशिक्षण केंद्र से तैयारी करके एमपी पीएससी की प्री परीक्षा में बैठने वाले 21 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इनमें सुरेश कुमार पटेल, वैशाली हरदा, विभावना हरदा, ललित पटेल, नरेंद्र कुमार पटेल, शिवकुमार बेस, सतीश जैन, विपिन सिंह, शुभम देशमुख, मोहम्मद नौशाद, ओमेंद्र विशेष, हेमंत गोटे, अक्षय पवार, रवि विश्वकर्मा, भारत नेमा, रोहित कौरव, नरेश दमाहे, सत्य कुमार साहू, गजेंद्र पाटीदार, कृष्णा खड़े, साक्षी ठाकुर एवं विनोद जायसवाल शामिल है। सहायक संचालक अवधेश सिंह के अनुसार इस परीक्षा में सौ उम्मीदवार बैठे थे, जिनमें से 21 सफल हुए हैं।

प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पांच फरवरी तक होगा सत्यापन

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण के बीच 18 जनवरी से प्रदेश के कॉलेज खुल चुके हैं। कॉलेजों में अब भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की भीड़ देखी जा रही है। लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को पांच फरवरी तक दस्तावेज सत्यापन कराने का समय दिया है। विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि विद्यार्थी उक्त समय में दस्तावेज जमा कर उनका सत्यापन नहीं कराते हैं तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि कॉलेजों में जनवरी के पहले सप्ताह तक नए सत्र के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। वहीं, कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया बंद हुए 15 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब भी करीब 30 फीसद विद्यार्थियों द्वारा कॉलेजों में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

प्रक्रिया

- **उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, जल्द पूरा कर लें नामांकन**
- **18 जनवरी से प्रदेश के कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन उपस्थिति कम है**

> अब भी कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसलिए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को दस्तावेज जमा करने और सत्यापन के लिए पांच फरवरी तक तारीख बढ़ाई गई है।
>
> **-डॉ. एम प्रसाद,** प्राचार्य, भेल कॉलेज

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शनिवार तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर पांच फरवरी कर दिया गया है। साथ ही विभाग ने पांच फरवरी तक कॉलेजों को सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के 471 कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के 450 से अधिक कॉलेज प्राचार्यविहीन संचालित हो रहे हैं। उनके स्थान पर कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर को प्रभारी नियुक्त कर काम चलाया जा रहा है। प्रदेश के 515 कॉलेजों में से 471 कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य हैं। राजधानी में 11 कॉलेजों में से आठ कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य हैं। कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य न होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अन्य स्टाफ भी उनके आदेश को नहीं मानते। राजधानी के सबसे बड़े स्वायत्तशासी नूतन कॉलेज में भी प्रभारी प्राचार्य हैं। वहीं एमएलवी, गीतांजलि, नवीन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बेनजीर व हमीदिया कॉलेज में भी प्रभारी प्राचार्य पदस्थ हैं, सिर्फ दो कॉलेज में स्थायी प्राचार्य हैं। बता दें, कि कॉलेजों में 2010 के बाद प्रोफेसरों को पदोन्नति नहीं दी गई। इसका कारण है कि आरक्षण और एकेडमिक ग्रेड पे को लेकर प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

प्रदेशभर में पीजी और यूजी कॉलेज मिलाकर प्राचार्यों के 471 कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य हैं और सिर्फ 44 कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य हैं। प्रदेश के पीजी कॉलेजों में प्राचार्य के 98 पदों में से 77 पद खाली हैं। वहीं यूजी कॉलेजों में 417 में से 394 पद खाली हैं। भोपाल के 11 कॉलेजों में से दो कॉलेजों में ही स्थायी प्राचार्य हैं बाकी प्रभारी के भरोसे चल रहा है।

इन कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य

नूतन कॉलेज- **डॉ. प्रतिभा सिंह**
एमएलवी कॉलेज- **निशा पालीवाल**
गीतांजलि कॉलेज-**अल्का डेविड**
हमीदिया कॉलेज -**पीके जैन**
बेनजीर कॉलेज - **सरोज श्रीवास्तव**
एमवीएम - **डॉ. महेंद्र सिंह**
नवीन कला महाविद्यालय- **राजीव वाघे**
शा.संस्कृत महाविद्यालय - **डॉ. पीके जमरा**

यहां स्थायी प्राचार्य

भेल कॉलेज - **डॉ. एम प्रसाद**
लॉ कॉलेज - **डॉ. सुधा बैसा**

> कॉलेजों में प्राचार्य के 75 फीसद पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन पदोन्नति का मामला न्यायालय में लंबित है। इस कारण कॉलेजों को स्थायी प्राचार्य नहीं मिल पा रहे हैं।
>
> **- अनुपम राजन,**
> प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

> साल 2010 के बाद प्रोफेसरों को पदोन्नति नहीं दी गई है। कारण यह है कि पदोन्नति को लेकर विवाद है और मामला कोर्ट में लंबित है।
>
> **- आनंद शर्मा,**
> महासचिव, प्राध्यापक संघ

माशिमं की 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल, 12वीं की 1 मई से

भोपाल | माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की सालाना परीक्षा 30 अप्रैल और हायर सेकंडरी 12वीं की परीक्षा 1 मई से होंगी। मंडल ने शनिवार को वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया। इनके पेपर सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षार्थियों को सुबह 7:30 बजे पहुंचना होगा। परीक्षा का कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध है। कोरोना की वजह से पहली बार मंडल की 10वीं-12वीं की परीक्षा इतनी देरी से होंगी। अब तक यह मार्च में होती थी।

सहोदया का सर्व • 20 हजार परीक्षार्थियों में से 12 हजार का औसत रिजल्ट 84% रहा

प्री-बोर्ड परीक्षा : ऑनलाइन क्लास अटेंड करने और स्कूल जाने से छात्रों का परफॉर्मेंस 24% बेहतर हुआ

विश्वनाथ सिंह | इंदौर

शहर के सीबीएसई स्कूलों में नौवीं और ग्यारहवीं के छात्रों की अर्द्धवार्षिक, 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं हाल ही में हुईं। इसमें जिन छात्रों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की और ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल भी पहुंचे उनका रिजल्ट क्लास अटेंड न करने वाले विद्यार्थियों से 25 प्रतिशत बेहतर रहा है। यह तथ्य सहोदया के सर्वे में सामने आया है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर से स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं।

इस सर्वे में शहर के 140 सीबीएसई स्कूल शामिल हैं। औसतन हर स्कूल में 10वीं-12वीं में 100-100 बच्चे हैं। इस लिहाज से दोनों कक्षाओं में 28 हजार विद्यार्थी हैं। ऑफलाइन प्री-बोर्ड परीक्षा में करीब 20 हजार ने भाग लिया। वहीं आठ हजार कोरोना संक्रमण या फिर अन्य किसी वजह से शामिल नहीं हुए। जो 20 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, उनमें 12 हजार ऐसे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के साथ ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल भी गए। इनका औसत रिजल्ट 84 प्रतिशत रहा। यह लॉकडाउन में हुई परीक्षाओं के औसत रिजल्ट 60 प्रतिशत से 24 प्रतिशत ज्यादा रहा। वहीं 8 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट 59 प्रतिशत रहा। ये ऐसे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने न ऑनलाइन क्लास अटेंड की और न ही ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल गए, यानी क्लास अटेंड करने वालों का रिजल्ट इससे 25 प्रतिशत अच्छा रहा।

140	सीबीएसई स्कूल हैं शहर में
28	हजार विद्यार्थी हैं दोनों कक्षाओं के
08	हजार कोरोना व अन्य कारणों से अनुपस्थित रहे

जो स्कूल नहीं आ रहे, उनका परफॉर्मेंस गिर रहा है

- हम लगातार पालकों से छात्रों को स्कूल भेजने को लेकर अनुरोध करते आ रहे हैं, लेकिन वे छात्रों को स्कूल भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में छात्रों का परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा है, जिसके कारण आगामी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट खराब होने की अंदेशा रहेगा।- **मोहित यादव**, प्रिंसिपल, एनी बेसेंट स्कूल

- 9वीं और 11वीं के छात्रों की प्री-एन्युअल एग्जाम ले रहे हैं। इसमें आने वाले छात्रों की संख्या केवल 60 प्रतिशत ही रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन व एग्जाम की तैयारी को लेकर आने वाले छात्रों का परिणाम काफी बेहतर रहा है। उनमें परीक्षा को लेकर डर भी कम हुआ है। संभवतः मुख्य परीक्षा में 100 प्रतिशत छात्र पहुंचेंगे। – **पिंकी जोशी**, प्रिंसिपल, सन्मति हायर सेकंडरी स्कूल

- जिन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की वे बच्चे परीक्षा देने भी नहीं आए। ऐसे में आगामी परीक्षाओं में उनके परिणाम पर असर देखने को मिल सकता है। हम छात्रों व पालकों की लगातार काउंसलिंग भी कर रहे हैं। –**अजय शर्मा**, प्रिंसिपल, डीपीएस

- सभी स्कूल इस समय कोविड-19 की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे में छात्र स्कूलों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पालकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और परीक्षाओं में शामिल कराना चाहिए। मुख्य परीक्षाएं सिर पर हैं, अगर वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका असर उन्हें बोर्ड परीक्षा के खराब परिणामों में देखने को मिल सकता है। – **यूके झा**, अध्यक्ष, सहोदया ग्रुप

डीएवीवी में 3 फरवरी से पहली बार परीक्षाओं के फॉर्म एक साथ होंगे जमा

फरवरी के आखिर में शुरू होंगी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं

भास्कर संवाददात| इंदौर

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की फरवरी-मार्च और अप्रैल में शुरू होने वाली सभी परीक्षाओं के फॉर्म 3 फरवरी से ऑनलाइन जमा होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं के फार्म एक साथ जमा होंगे। यूनिवर्सिटी इसी का सिस्टम तैयार कर रही है। इसमें दो दिन का वक्त लगेगा। यूनिवर्सिटी की कोशिश है कि मंगलवार से ऑनलाइन परीक्षा फार्म जमा होना शुरू हो जाएं। परंपरागत से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक के फार्म एक साथ जमा होंगे। एक्जाम कंट्रोलर डॉ. अशेष तिवारी के अनुसार तैयारी पूरी हो गई है। पूरा शेड्यूल जल्द जारी होगी ।

इन परीक्षाओं की है तैयारी

यूनिवर्सिटी में 25 फरवरी से परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा। जिन परीक्षाओं के फार्म जमा होना है उनमें बीबीए-बीसीए पहले, तीसरे और पांचवे सेमेस्टर के अलावा एमबीए प्रथम, तृतीय सेमेस्टर, एमए, एमकॉम और एमएससी पहले, तीसरे सेमेस्टर शामिल हैं। इसके अलावा कुल 32 परीक्षाएं भी मार्च में ही होंगी। उसके परीक्षा फार्म भी साथ ही जमा हो रहे हैं। इसमें बीएड पहले और तीसरे सेमेस्टर के साथ बीजेएमसी सहित अन्य स्पेशलाइजेशन कोर्स शामिल हैं। तैयारी तो यह भी है कि अप्रैल-मई में संभावित बीकॉम, बीए और बीएससी पहले, दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए भी अभी फार्म जमा हो जाएं। हर साल यह एक्जाम 1 मार्च के आसपास आरंभ होती है। लेकिन इस बार कोरोना संकट का असर पढ़ाई पर पड़ा है।

विज्ञान दिवसः आईआईटी करेगा लेक्चर सीरीज

इंदौर | राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आईआईटी इंदौर लेक्चर सीरीज कर रहा है। ऑनलाइन होने वाली केमिस्ट्री लेक्चर्स नामक सीरीज के तहत फरवरी में हर सप्ताह एक ख्यात अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञानी संबोधित करेंगे। आईआईटी के अनुसार 4, 11, 16 और 26 फरवरी को विदेश से आए प्रोफेसर लेक्चर देंगे। आईआईटी के अनुसार केमिस्ट्री लेक्चर्स का मकसद दुनियाभर के वैज्ञानिकों को केमिकल साइंस और उससे जुड़े क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं को साझा करना और उन पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है।

प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 5 फरवरी तक

विद्यार्थियों ने छह दिन में दस्तावेज जमा नहीं कराए तो नहीं मिलेगा प्रवेश

भोपाल। कोरोना संक्रमण के कारण 18 जनवरी से प्रदेश के कॉलेज खुल चुके हैं। कॉलेजों में अब भी प्रथम वर्ष के विद्यर्थियों की भीड़ देखी जा रही है। अगर अब छह दिनों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी दस्तावेज जमा नहीं किए और सत्यापन नहीं कराया तो एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। कॉलेजों में जनवरी पहले सप्ताह तक नए सत्र के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। वहीं कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया बंद हुए 15 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी करीब 30 फीसद विद्यार्थियों द्वारा अब भी कॉलेज में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शनिवार तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

ऑनलाइन हुई प्रवेश प्रक्रिया

वहीं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद कॉलेज में काउंसिलिंग 6 चरण प्रक्रिया को जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा कर लिया गया था। वहीं इस बार प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हुई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा विद्यर्थियों के जरूरी दस्तावेज मंगवाए गए थे। इसके बावजूद इसके कॉलेज एडमिशन के 30 फीसद विद्यार्थियों द्वारा अभी दस्तावेज जैसे टीसी और माइग्रेशन सहित जाति प्रमाण पत्र कॉलेज को नहीं सौंपे गए हैं। यदि विद्यार्थियों द्वारा दो दिन के भीतर जरूरी दस्तावेज की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उनका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा।

गुरू-शिष्य परम्परा के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित

रीवा। मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी की ओर से गुरू-शिष्य परम्परा के तहत ध्रुपद गायन का प्रशिक्षण ध्रुपद केन्द्र में दिया जायेगा। केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 की गई है। पूर्व में आवेदन जमा करने की तिथि 31 जनवरी 2021 थी। प्रशिक्षण की अवधि चार वर्ष रहेगी। चयनित प्रतिभागी को प्रतिमाह 3 हजार रुपए बतौर छात्रवृत्ति प्रशिक्षण अवधि में दी जायेगी। आवेदक की उम्र 16 से 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परम्परा प्रतिष्ठित है।

शिवराज ने सागर में किया समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का वायदा

कर्जमाफी का ब्याज भरेगी सरकार

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल/सागर

कर्ज माफी के दौरान सिर पर ब्याज का जो बोझ आ गया है, वह सरकार चुकाएगी। किसानों को यह भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वह सागर के खेल परिसर के समीप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों को सिंगल क्लिक से 400 करोड़ रुपये के हितलाभ अंतरण के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। फरवरी और मार्च में भी 400-400 करोड़ रुपये किसानों के खातों में डालने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने यहां समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनाने का वायदा भी किया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये डालने की शुरुआत की थी। तत्कालीन सरकार ने किसानों की सूची केन्द्र को नहीं भेजी थी। हमने सरकार में आते ही 78 लाख किसानों की सूची भेजी और यह निर्णय लिया कि किसानों के खातों में दो किस्तों में 4 हजार रुपये अतिरिक्त डाले जाएं। सरकार ने किसानों के खातों में राशि डालने में कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे आधा एकड़ का किसान हों या एक एकड़ का, सभी को दोनों योजनाओं में साल में 10 हजार रुपये खाते में डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में तंगी होने के बावजूद भी अलग-अलग योजनाओं में 85 हजार करोड़ रुपये किसानों और अन्य हितग्राहियों के खाते में डाले गए। उनका यहां कहना था कि फिलहाल 41 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। आने वाले दिनों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले बुन्देलखण्ड में ही 8 हजार 644 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएँ चल रही हैं। केन-बेतवा नदी जोड़े जाने की भी जानकारी देते हुए कहा कि इससे पूरा बुन्देलखण्ड सिंचित हो जाएगा।

कांट्रैक्ट फार्मिंग से क्या दिक्कत

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कानून बनाए हैं। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो क्या दिक्कत है। हमारे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। इससे पहले उन्होंने कहा कि मण्डी बंद नहीं की जा रही है वरन मण्डी शुल्क घटाया गया है। किसानों की सहूलियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब किसान को सीमांकन की सुविधा मोबाईल डिवाईस से मिलेगी। राजस्व सिस्टम आधुनिक बनाया गया है, जिसे आरसीएमएस कहा जाता है। अब पेशी की जानकारी एसएमएस से भेजी जाती है। जमीन का नामांतरण, बँटवारा की प्रक्रिया सरल और कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है।

लाभांवित हुए हितग्राही

मुख्यमंत्री ने अनेक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभांवित किया। स्व-सहायता समूह को रुपये 1 करोड़ 49 लाख का स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान अशोक दुबे, हरिनारायण को दो-दो हजार के चेक, हितग्राही पूरनलाल को मकान की चाबी, शफीक को ऑटो की चाबी, किरण सैनी स्व-सहायता समूह को दुकान की चाबी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत गुल्ली-चेतु को 10 हजार का स्वीकृति पत्र सहित अन्य हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दिव्या अशोक सिंह एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यह थे मौजूद

कार्यक्रम में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, कृषि मंत्री कमल पटेल, पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल, सांसद राजबहादुर सिंह, पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण यादव, सागर विधायक शैलेन्द्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, बीना विधायक महेश राय सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

बीयू में लागू होगा स्टूडेंट चार्टर, छात्रों की समस्या समय पर हल नहीं होने पर सजा का भी प्रावधान

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में डेढ़ दर्जन मुद्दों पर चर्चा

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में स्टूडेंट्स की 26 तरह की समस्याओं को समय सीमा में हल करने के लिए स्टूडेंट चार्टर लागू करने की तैयारी है।

बीयू की शनिवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में इस पर चर्चा हुई। ईसी की बैठक में लगभग डेढ़ दर्जन अन्य प्रस्ताव रखे गए, जिन पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। ज्ञात हो कि ईसी मेंबर किशन सूर्यवंशी ने पिछली बैठक में स्टूडेंट चार्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि उसमें समय सीमा में छात्रों की समस्या हल नहीं होने पर अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सजा का प्रावधान नहीं होने से इसे संशोधित कर अगली बैठक में रखने को कहा गया है। इसमें छात्रों से जुड़ी 26

प्रकार की सुविधाएं चिह्नित की गई हैं। बैठक में 11 साल पुराने केबल के 3 लाख 90 हजार रुपए के भुगतान का प्रस्ताव रखा गया। इसकी ओरिजनल फाइल के बजाय फोटोकॉपी पेश करने के कारण ईसी ने कुलपति को अधिकृत किया है कि इसका अध्ययन कर अगली बैठक में रखें। बीयू द्वारा पूर्व में 12 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा करने का मामला भी बैठक में रखा गया, जिसमें ईसी ने कंसल्टेंट रखे जाने का आदेश दिया, ताकि इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी न हो।

अब 65 के बजाय 62 वर्ष में रिटायर होंगी प्रो. शुक्ला

अंबेडकर विवि की कुलपति प्रो. आशा शुक्ला को छानबीन समिति ने प्रोफेसर के बजाय परियोजना अधिकारी बताया है। इस पर ईसी ने भी मुहर लगा दी। अब वह 65 के बजाय 62 वर्ष में रिटायर होंगी। हालांकि कुलपति पद पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रो. शुक्ला कुलपति बनने से पूर्व बीयू के महिला अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष थीं। उनके प्रोफेसर होने पर विवाद था।

प्लेसमेंट सेल बनेगी: ईसी में प्लेसमेंट अधिकारी नरेन्द्र रघुवंशी की 25 हजार से 35 हजार रुपए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। ईसी ने सहमति दे दी। बीयू में पिछले वर्षों में छात्रों का कोई खास प्लेसमेंट नहीं होने पर ईसी ने प्लेसमेंट सेल बनाने के निर्देश दिए।

भास्कर Original विशेषज्ञों से जानिए कैसे सुधर सकता है मार्केट सेंटीमेंट

ड्रीम बजट : दोगुनी हो आयकर छूट की सीमा... अब सभी हों आयुष्मान

कोरोनाकाल में पहले बजट से जनता को छूट, सरकार को कमाई बढ़ने की आस

धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया | नई दिल्ली

आर्थिक समीक्षा देश की अर्थव्यवस्था की रिकवरी की बेहतर तस्वीर पेश करती है। इस बेहतर तस्वीर को सच करने के लिए जरूरी है कि आम बजट में सरकार कदम भी ऐसे ही उठाए। कोरोनाकाल में पहला बजट आखिर कैसा हो इस पर दैनिक भास्कर ने विशेषज्ञों से बात की। भास्कर एक्सपर्ट पैनल का कहना है कि आगामी वित्त वर्ष में 11% की ग्रोथ रेट की जो उम्मीद आर्थिक सर्वेक्षण में जताई गई है उसे पाने के लिए न सिर्फ सरकार को कमाई बढ़ानी होगी बल्कि एक भयमुक्त माहौल भी बनाना होगा।

इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम के सर्वे में भी सामने आया है कि सरकार की प्राथमिकता हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर रह सकती है। भास्कर विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद है कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए ताकि खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आए। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के दायरे में अब सभी को लाया जाए ताकि सेहत की चिंता से भी जनता को मुक्ति मिले। मगर ऐसी घोषणाओं के लिए जरूरी है कि सरकार अपनी कमाई भी बढ़ाए। जानिए कैसे अर्थव्यवस्था को उबारने के उपायों के साथ सरकार आय बढ़ा सकती है।

उम्मीदें 2021-22 : टैक्स का बोझ घटे तो खर्च के लिए मिले ज्यादा

आयकर : छूट की सीमा 5 लाख हो, होम लोन पर ब्याज छूट सीमा भी बढ़े

अभी कर मुक्त सीमा जो 2.5 लाख रुपए की है वह बढ़कर पांच लाख रुपए होनी चाहिए। होमलोन पर ब्याज की छूट भी 3.5 लाख से बढ़कर पांच लाख रुपए होनी चाहिए। मेडिक्लेम सीमा 75 हजार से बढ़कर 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। साथ ही सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिसिन पर कर का बोझ घटाना चाहिए। एमएसएमई और कॉर्पोरेट कर को भी तर्क संगत बनाना चाहिए।

स्वास्थ्य : आयुष्मान का दायरा बढ़े, गांव में अस्पताल खोलने पर इंसेंटिव

स्वास्थ्य पर अभी जीडीपी के एक फीसदी से भी कम खर्च हो रहा है जबकि यह कम से कम तीन फीसदी होना चाहिए। केंद्र सरकार का हेल्थ बजट 67,111.8 करोड़ रुपए है। इसे दोगुना होना चाहिए। गांव और छोटे शहरों में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं ले जाने पर इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। पीएम जेएवाय का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी को शामिल करना चाहिए।

इंफ्रास्ट्रक्चर : अलग से बैंक की स्थापना हो, सरकार खुद निवेश बढ़ाए

उम्मीद है कि वित्त मंत्री रोड, हाईवे और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभागीय बजट आवंटन बड़ी मात्रा में बढ़ाएंगी। सरकार ने सौ लाख करोड़ रुपए से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पांच वर्ष के लिए घोषित किया है। सरकार को आवंटन कम से कम 50% बढ़ाना चाहिए और सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फंड लगाना चाहिए। एसोचैम ने अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की मांग भी की है।

कृषि: पीएम किसान सम्मान निधि छह हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए हो

मौजूदा समय में रूरल डिमांड बढ़ाने की आवश्यकता है। पीएम किसान सम्मान निधि जिसमें अभी छह हजार रुपए वार्षिक मिलता है उसमें कम से कम 18 हजार रुपए मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए। सितंबर में सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स के लिए सेस कंपन्सेशन दिया था तो इसे भी दिया जा सकता है।

कैसे आएगा पैसा : खर्च के लिए इंफ्रा बॉन्ड लाए सरकार, बेहतर जीडीपी ग्रोथ से बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन...विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करे तो बढ़े कमाई

जैसा कि आर्थिक सर्वे में भी कहा गया है कि सरकार को खर्च बढ़ाना होगा तभी जीडीपी ग्रोथ आएगी। सरकार बजटीय घाटे को बढ़ाकर 5.5 से 6% कर सकती है। वहीं दूसरी ओर जीडीपी में ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी इसके कारण टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा। सरकार इस बार विनिवेश से भी पैसा ला पाएगी क्योंकि बीते दो वर्षों में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है और सरकार की तैयारी इस दिशा में बेहतर हो गई है। इससे दो लाख करोड़ से अधिक रुपए आ सकते हैं। सरकार इंफ्रा बांड और रिटेल बॉन्ड जारी कर पैसा बाजार से आमंत्रित कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोजेक्ट विशेष के लिए फंड की व्यवस्था की जा सकती है।

भास्कर एक्सपर्ट पैनल : **विनीत अग्रवाल**, प्रेसिडेंट एसोचैम | **वाईके अलघ**, पूर्व केंद्रीय मंत्री | **डॉ. राना मेहता**- पार्टनर-लीडर हेल्थ केयर पीडब्ल्यूसी इंडिया | **डी.के. जोशी**, चीफ इकॉनामिस्ट क्रिसिल इंडिया | **देविंदर शर्मा**, कृषि विशेषज्ञ | **सीए देवराजा रेड्डी**, पूर्व प्रेसीडेंट आईसीएआई

आज का इतिहास

- 1561: मुगल सेना के सेनापति बैरम खां की गुजरात के पाटन में हत्या।
- 1893: 'कोका कोला' ट्रेडमार्क का अमेरिका में पहली बार पेटेंट हुआ।
- 1915: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया ।
- 1946: तत्कालीन सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर यूगोस्लाविया का छह देशों में विघटन (सर्बिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, मैसेडोनिया)
- 1953: आईरिश सागर में नौका दुर्घटना में कम से कम 130 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई।
- 1961: बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह का निधन।
- 1963: मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
- 1966: सोवियत संघ ने लूना कार्यक्रम के तहत मानवरहित लूना नौ अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया।